

न्यायालय जिला कलेक्टर, (लोक अदालत), दौसा

दौसा जिला अधिकारी- नरेश कुमार शर्मा, आई0ए0एस0

अपील सं0 41/2018

नरसिंहलाल पुत्र सांवलराम जाति मीना निवासी ग्राम रामसिंहपुरा तहसील दौसा जिला दौसा

...अपी0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा

...रेस्पो0

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.10.2017
व न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा

उपस्थित :1. अपीलांत स्वयं

2. श्री चंद्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 13.06.2018

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार दौसा ने दिनांक 18.10.2017 को ग्राम रामसिंहपुरा तहसील दौसा के आराजी खसरा नम्बर 111 रकबा 0.04 है0 किस्म भूमि चरागाह पर अपीलांत को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस का सिविल कारावास का आदेश पारित कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान सरकार (राजस्व ग्रुप-1) विभाग के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन कर प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत किया गया।

अपीलांत द्वारा लोक अदालत में उपस्थित होकर बहस में निवेदन किया कि मेरे द्वारा अतिक्रमित भूमि से कब्जा हटा लिया है। अपीलांत का मौके पर कब्जा नहीं है। अपीलांत द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किया जाने में सहमति प्रकट की। प्रकरण का गुणावगुण व शपथ पत्र के आधार पर लोक अदालत की भावना के अनुसार न्यायहित में सिविल कारावास का आदेश निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश में से सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांत द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांत द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 13 जून, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित छुले न्यायालय सुनाया गया।

